पहले पेज से आगे

मॉस्को रेत कला स्पर्धा, सुदर्शन को गोल्ड

देशों के 25 मूर्तिकारों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी अद्भुत कला का लोहा दुनिया भर में मनवा लिया है।

सुदर्शन पटनायक भारत के ओडिशा के प्रसिद्ध रेत-कलाकार हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। वे सम-सामयिक विषयों पर अक्सर रेत से कलाकृतियां बनाकर उन्हें नए रूप में प्रस्तुत करते हैं।

सुदर्शन पटनायक को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं जिनमें 2014 में पद्मश्री के साथ साल 2008 में ओडिशा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला 'सारला' अवार्ड भी शामिल है। साल 2015 में सुदर्शन ने पुरी के समंदर के किनारे सबसे बड़ा रेत का सांता क्लॉज बनाया था जिसे उसे लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स में जगह मिली थी। सुदर्शन रेत-कलाकारी में 9 बार लिम्का बुक ऑफ़ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं जबकि विदेश में सैकड़ों ईनाम जीत चुके हैं। सुदर्शन ओड़िशा अंतरराष्ट्रीय रेत-कला उत्सव के ब्रांड एम्बैसेडर भी हैं

सुदर्शन पटनायक रेत-कला के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और इसके लिए अपनी कला का इस्तेमाल से दुनिया में शांति के के संदेश रेत पर उकेरते हैं। आतंकवाद, एड्स, धूम्रपान, मानवता, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर अक्सर रेत शिल्प बनाते हैं। सुदर्शन पटनायक पुरी में 'सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टिट्यूट' इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पूरी दुनिया से बच्चे रेत-कला सीखते हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा- मोदी के दौरे को लेकर गुमराह न हो

मोदी इसमें हिस्सा लेने अगले हफ्ते श्रीलंका आने वाले हैं। सिरिसेना ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो इन झूठी कहानियों से गुमराह नहीं हों कि भारत समझौतों के माध्यम से हमारे देश के इलाके ले लेगा।

उन्होंने ये बात त्रिंकोमाली गोदी में सामरिक महत्व वाली तेल भंडारण सुविधा के संयुक्त संचालन के लिए भारत के साथ प्रस्तावित समझौते पर लोगों की आपत्तियों के मद्देनजर कही। श्रीलंका की सरकारी स्वामित्व वाली पेट्रोलियम कंपनी के श्रमिकों ने सामरिक महत्व वाली तेल भंडारण सुविधा के संयुक्त संचालन के लिए भारत के साथ प्रस्तावित समझौते के विरोध में पिछले हफ्ते हड़ताल की थी। सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध काल के तेल टैंकों के विकास के लिए भारत के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए समझौता करने की योजना की घोषणा की है।

मप्र में दलित ने छुआ ऊंची जाति का कुआं, तो केरोसिन डाला

पुलिस आर एस मीणा ने बताया कि वे शनिवार गांव में गए और उसी कुएं से पानी पिया जिससे दलितों ने इस्तेमाल किया था। यही नहीं, उन्होंने ऊंची जाति के लोगों को समझाया। कलेक्टर ने ये भी कहा कि उस इलाके में दो पानी की बोरवेल लगाई जाएगी ताकि आने वाले समय में दोनों जातियों को कोई दिक्कत न हो। कलेक्टर मे कहा, पुलिस मामले की जांच कर रही है और हालातों पर नजर बनाए हुए है।

23 अप्रैल को 45 साल के दलित चंदेर मेघवल ने लड़के वालों का स्वागत बैंड बाजे से किया था, जबकि उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद उसने बैंड वाले को शादी में बुलाया। दरअसल, गांव की परंपार के मुताबिक दलित केवल शादियों में ढोल ही बता सकते हैं।

दिमाग से भी लालबत्ती जानी चाहिए

श्रमिकों के कल्याण के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। जगत गुरु बश्वेश्वर ने भी श्रम श्रमिक पर गहन विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि अपने घर पर परिश्रम से भगवान प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा था कि श्रम ही ईश्वर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र करते हुए कहा कि बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक है।

गौरतलब हो कि 30 वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से बदलाव का अह्वान किया था। उन्होंने न्यू इंडिया के बारे में बात करते हुए कहा था कि सभी देशवासी अगर संकल्प करें और मिलकर कदम उठाते चलें, तो न्यू इंडिया का सपना हमारे सामने सच हो सकता है। हर कोई अपने नागरिक धर्म और कर्तव्य का पालन करे, यही अपने आप में न्यू इंडिया की एक अच्छी शुरुआत बन सकता है।

पेज 7 से आगे

हिंसा खत्म नहीं होती क्योंकि वह

हर हिंसक कार्रवाई, हर हमला कायरतापूर्ण है। वीरता और कायरता की इस दुविधा के कारण ही जवानों की मौत के बाद यह बताना जरूरी हो गया कि जवानों ने भी माओवादियों का जवाब दिया और उनके लोग मारे। सीआरपीएफ के हथियार लूट लिए गए, यह अलग से शर्म की बात मानी जाएगी। माओवादी समूह यह कहकर उत्तर देंगे कि यह युद्ध है और युद्ध में सब जायज है। दिलचस्प यह है कि सरकार भी इसे युद्ध ही कहना चाहती है। इस हिंसक स्थति को युद्ध कह देने पर दोनों पक्षों को अलग-अलग तरीके की हिंसा को जायज ठहराने का आधार मिल जाता है।

निरंतर सड़क बनाने और निगरानी के उपाय करने की बेचैनी दरअसल इस 'युद्ध' में हर इंच जमीन पर अपने प्रभुत्व की घोषणा से जुडी है। जो भी पक्ष हो या प्रतिपक्ष, वह इस घोषणा को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में हिंसा का यह चक्रभी रुक नहीं सकता। इसकी तीव्रता या निरंतरता में कमीबेशी भले हो।

पहला कदम हिंसा को नामंजूर करने का होगा। यह पहले कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है। क्या अपनी ओर से हिंसा की समाप्ति की घोषणा अनिवार्यत: पराजय की घोषणा ही है? (सत्याग्रह)

आजादी के 70 साल, आदिवासी और नक्सली में फर्क क्यों नहीं?

और आदिवासी ग्रामीण महिलाओं के क्षत विक्षक शव। क्या ऐसे होते हैं माओवादी? क्या इंसानियत इस देश में मर गया है क्या? बंद करो इस प्रकार का खेल जो इंसानियत को शर्मसार करता है।

एक और घृणित खेल आदिवासी क्षेत्रों में वर्षों से चल रहा है और वह है धर्म का खेल। सब जानते हैं कि भारत के आदिवासी वर्णव्यवस्था से परे प्रकृति के आराधक है उन्हें किसी विशेष धर्म से जोड़ने की पूरी मुहीम चल रही आदिवासी क्षेत्रो में जिसे अब बंद किया जाना चाहिए।

भारत के वीर आदिवासियों को कभी भी उनके राष्ट्रभक्ति और उनके असीम देशप्रेम को दुनिया के सम्मुख उजागर नहीं किया गया। आज भारत में भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद की बात सब करते हैं लेकिन बाबा तिल्का मांझी, बिरसा मुंडा, सिधू-कान्हू मुर्मू के बारे में आज की पीढ़ी कुछ नहीं जानते! सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं आदिवासी वीरों के जिन्होंने अपनी जान दी है इस देश के लिए। अपनी स्वतंत्रता के लिए सर्वप्रथम 'आदिवासी नायकों' ने बिगुल फूका था। भील, गौंड, मुंडा, संताल, उरांव, पहाड़िया, मीणा मैं किन-किन वीर आदिवासियों का उदाहरण दूँ। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे वीरों के शहादत से लेकिन कभी गैर-आदिवासी समाज में उनकी चर्चा तक नहीं की गई। भारत की आजादी के उपरान्त किसी भी राजनितिक दल ने उन महान आदिवासी नायकों की महिमा तक नहीं की! क्या वे सभी वीर 'आदिवासी नायक' अपने देश भारत से प्यार नहीं करते थे? फिर कुछ लोग किस संस्कृति की बात करते हैं?

विकास की प्रक्रिया हमेशा सरलता से जटिलता की ओर होती है, ना की जटिलता से सरलता की ओर! हमारी प्राकृतिक भाषा मुंडा, खड़िया, संताली, गौंड और कुड़ुख भाषा की सरलता पूरा विश्व जानता है लेकिन कोई इस बात के लिए दावा कैसे कर सकता है कि भारत के अन्य भाषाओं की जननी जटिल भाषा 'संस्कृत' है। यह तो थोपने जैसे बात हुई। किसी देश को 'राष्ट्र' यानी नेटशन उसकी अपनी भाषा ही बना सकती है और आदिवासियों की भाषा एवं विशेष संस्कृति-परम्परा ही भारत को एक राष्ट्र यानी नेटशन बना सकता है।

'वैदिक काल' से पूर्व क्या भारत में सभ्यताएं विकसित नहीं थी? क्या यहां मूल लोग निवास नहीं करते थे? और क्या उन लोगों की कोई भाषा नहीं थी? या फिर वे लोग गूंगे थे जो सिर्फ इशारों से बात किया करते थे? फिर ये आदिवासी समुदाय, वैदिक सभ्यता से कैसे अछूते रह गये! आदिवासियों की भाषाओं का संस्कृत और अपभ्रंश भाषा परिवार से कोई सम्बंध नही है। भारत के हो, मुंडा, संताल, खड़ीया, गौंडवी, उरांव भाषाए क्या संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं? अगर नहीं तो फिर संस्कृत सभी भारतीय भाषा की जननी कैसे हुई? भारत के संविधान के 'अनुसूची आठ' में संताली भाषा को 2003 मे शामिल किया गया। भारतीय मुद्रा मे अंकित 22 राष्ट्रीय भाषाओं मे आदिवासी भाषा संताली को शामिल किया गया है। वर्ष 1949 मे संताली भाषा और लिपि ओल चिकी को पूरे मयूरभंज राज्य मे लागू किया जाना था। लेकिन आजादी के बाद भी मयूरभंज का संताल समुदाय अपनी भाषा और लिपि के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है।

क्या ही विडम्बना है आज अपने ही देश में आदिवासी समुदाय अपने पहचान के लिए निरंतर संघर्षरत है। इस बात से कोई भी राजनीतिक दल हम आदिवासियों से किनारा नहीं कर सकते कि 1947 से हम आदिवासियों की परिभाषा देने का प्रयास करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक हमारी पूर्ण परिभाषा नहीं दे पाए हैं। जब एन में पूछा गया कि क्या आदिवासी समुदाय भारत में पाये जाते हैं ? तो भारत के प्रतिनिधियों ने यह कह कर साफ इंकार कर दिया और कहा कि आदिवासी किसी जमाने में रहा करते थे, वर्तमान में यहां जनजाति लोग रहते हैं जिसके मूलता में ही संदेह है!

क्या कमाल की तस्वीर बनाई है आपने भारत के आदिवासियों की! आज हमारे रंग-रूप कद-काठी, वेश- भूषा, भाषा संस्कृति कुछ जीवित रहते हुए भी आदिवासियों को अतीत (भूतकाल) बना दिया। यहां तक की आदिवासियों को उनके ही देश के संविधान से बाहर निकाल दिया और चंद समय काल के लिए जनजाति बना दिया। भारत के पूरे अनुसूची पांच क्षेत्र की जनजाति अपने आपको 'आदिवासी' कहती है तो फिर इस शब्द से इतनी नफरत क्यों?

यह बात सभी जानते हैं आदिवासी ही भारत के मूलवासी हैं। लेकिन वर्षों से आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता कहें या उद्देश्य वे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। समय-समय पर आदिवसियों को गिरिजन, जंगली, असभ्य, वनवासी वगैरह वगैरह तक कहा, लेकिन आदिवासी के नाम पर विश्व समुदायों के सामने इंकार किया जाता है क्या यह दोगलापन नहीं है? या फिर कुछ लोगों को अपने मूल होने की शंका होने लगी है।

जबरदस्ती आदिवासियों को 'हिन्दू' प्रमाणित करने की पूरी कोशिश जारी है जबकि दुनिया को पता है कि आदिवासी समुदाय 'वर्ण' और 'धर्म' से परे एक ऐसा समाज जहां सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है कोई ऊंच नीच के किसी भी सिद्धान्तों को नहीं मानते। अगर कोई आदिवासी समुदायों को हिन्दू मानते भी हैं तो आजतक यह ज्ञात क्यूं नहीं हुआ कि आदिवासियों का वर्ण क्या था? और किस श्रेणी में उन्हे रखा गया था? आदिवासी- ब्राह्मण ! क्षत्रिय ! वेश्य! या शूद्र आदि वर्णों मे किस वर्ण मे शामिल किया था और यह बात आज तक क्यूं छुपा कर रखा गया?

वोट बैंक की राजनीति और सत्ता के चक्कर में आदिवासियों को आर्थिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व के लिये 15 फीसदी आरक्षण दस वर्षों के लिए दिया गया और कहा गया कि पहले शिक्षित हो जाएं फिर शासन करने की बात करें! लेकिन बड़ी चालाकी से हर बार आरक्षण बिल में संशोधन करके आरक्षण की अवधि बढ़ा दी जाती है ताकि आदिवासी अपने स्वशासन की बात ही ना कर सके। कुछ लोग इस देश मे बात करते हैं 'राष्ट्रवाद' की और सहिष्णुता की! आदिवासी समाज वर्षों से सब कुछ सहते आ रहा है। 'सहिष्णुता' का सबसे बड़ा उदाहरण तो आदिवासी समुदाय है। लेकिन हर चीज की अपनी सीमा होती है। अब आदिवासी समुदाय जागृत हो रहा है। आजादी के बाद से आदिवासियों के साथ खेले गए हर कूटनीति और राजनीति को समझ रहे हैं। जो मूल है उसे झूठ के आवरण में कब तक रखा जा सकता है? आदिवासी समुदाय ही इस देश के 'मूल' और 'ओरिजिनल' हैं यही कारण है कि आज तक आदिवासी संस्कृति और सभ्यताएं सड़ी नहीं, जो हाइब्रिड होते हैं वह जल्द सड़ जाते हैं। (यूथ की आवाज)

पेज 9 से आगे

नेशनल शूटर, रिटायर्ड कर्नल के घर छापा

दिल्ली से आई इस टीम ने छापेमारी की कार्रवाई शनिवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे शुरु की जो रविवार सुबह 3:30 बजे तक चली। छापेमारी की कार्रवाई में दिल्ली से आई टीम सहित वन विभाग के आला अधिकारियों और पुलिस टीम को भी बुलाया गया था।

एकमात्र तैरती झील लोकटक

पहले ऋतु अनुसार फूमदियां डूबती-उतराती थीं; अब पार्क में अक्सर बाढ़ का ही दृश्य रहता है। पहले पार्क में नरकुल क्षेत्र ही था। परियोजना बनने के बाद से पार्क का एक-तिहाई हिस्सा पानी में डूबा रहता है और दो-तिहाई इलाका फूमदी क्षेत्र है। माना जा रहा है कि लगातार बनी बाढ़ के कारण ही फूमदियों की मोटाई में गिरावट आई है; वनस्पतियों की वृद्धि दुष्प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों को भोजन देने वाली वनस्पतियों और मछलियों का संकट भी इस बैराज ने बढ़ाया है। खासकर छोटे जीवों पर तो संकट बढ़ा ही है।

वनस्पतियों की वृद्धि को स्थानीय लोकटक पनबिजली परियोजना ने एक और तरह से दुष्प्रभावित किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहले जब स्थानीय नदी - खोरदक तथा अन्य धाराओं में बाढ़ आती थी, तो उनका प्रवाह उलट जाता था। वह उलटा प्रवाह आकर लोकटक की सतह पर फैल जाता था। नदियों से आया यह जल कई ऐसे पोषक और धातु तत्व अपने साथ लाता था, जो सूखे मौसम में नीचे जमकर उर्वरा क्षमता बढ़ाते थे। वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी होती थी; अब कम होती है।

नगरीय प्रदूषण, रासायनिक खेती का प्रदूषण वन कटान, मिट्टी कटान, वनस्पतियों के सड़ने और फूमदियों के ऊपर तक डूबे रहने के कारण लोकटक झील के पानी की गुणवत्ता में भी कमी दर्ज की गई है। एक जांच में लोकटक के पानी का पीएच मान 04 से 08.5 तक पाया गया। चिंतित करता सवाल है कि इन सब कारणों से यदि फूमदी नष्ट होती रही, तो एकमात्र तैरती झील और पार्क का रुतबा कब तक बचेगा ?

मूल कारण पर हो ध्यान

समाधान के तौर पर अधिक ऊंचाई वाले ऐसे स्थानों का निर्माण सुझाया गया है, जीव जहां निवास कर सकें। शोध, प्रशिक्षण, जन-जागृति अभियान, पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन, ईंधन पर पाबंदी जैसे उपाय भी सुझाए गए हैं। क्या गजब की बात है जो समस्या परियोजनाओं ने पैदा की है, हम उसका समाधान शोध, प्रशिक्षण, जागृति और पर्यटन में खोज रहे हैं। भारत में आजकल यही हो रहा है। पहले समस्या पैदा करो, फिर उसका समाधान करने के लिए प्रोजेक्ट बनाओ, पैसा खपाओ; किंतु समस्या के मूल कारण को यथावत बना रहने दो। कई अन्य की तरह इथाई बैराज भी कुदरती संपदाओं को बर्बादी की ओर ले जाती हमारी बेसमझी का एक नमूना है। इस बेसमझी को और गहरे से समझना तथा समाधान की आवाज उठाना भी लोकटक भ्रमण का एक उद्देश्य हो सकता है। कभी चलिए।

पेज 12 से आगे

सुकमा में नक्सली हमले के बाद आस-पास के गाँव खाली

जवानों ने गाँव की महिलाओं को भी पीटा। दरअसल सुरक्षा बलों से जिस दिन माओवादियों की मुठभेड़ हुई थी उस दिन माओवादी छापामारों ने गाँव की तरफ से भी हमला किया था।

महिलाएं बताती हैं कि सुरक्षा बल के जवान गाँव वालों को कह रहे थे कि उन्होंने ही माओवादियों को अपने घरों में पनाह दी थी।

डर में है ज़िंदगी

लेकिन गाँव की महिलाएं इन आरोपों का खंडन करती हैं। उनका कहना है कि सैकड़ों की संख्या में जब हथियारबंद माओवादी गाँव में घुसे तो वो लोग उनका विरोध भला कैसे कर सकते थे।

मगर सुरक्षा बल के जवान उनकी एक सुनने को तैयार नहीं हैं। वो मानते हैं कि बिना किसी गाँव वाले की मदद के माओवादी वहां शरण नहीं ले सकते थे।

सुरक्षा बलों के जवानों के बाद गाँव में माओवादी भी आ धमके और उन्होंने भी गाँव के लोगों को धमकाया। गाँव की महिलाएं कहतीं हैं कि माओवादियों ने उन्हें गाँव से चले जाने का फरमान जारी किया।

बुर्कापाल गाँव खाली हो चुका है क्योंकि यहाँ रहने वालों ने कहीं दूर जाकर शरण ले रखी है।

मगर गाँव में जो इक्का-दुक्का बुज़ुर्ग और महिलाएं बचीं हैं वो खौफ़ में जी रही हैं। उन्हें एक बार फिर किसी अनहोनी का अंदेशा सता रहा है।

पेट्रोल पंपों पर 10-15 % ठगी

रवींद्र ने पूछताछ में बताया कि वह इस चिप को लगाने के लिए पेट्रोल पंप मालिक से 40 से 50 हजार रुपए तक लेता था। उससे जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ ने पांच और पेट्रोल पंपों पर छापा मारा था। मुरादाबाद से दो इंजीनियर्स को पकड़ा गया था।

एक अधिकारी ने पहले बताया था कि इस गोरखधंधे के पीछे एक बहुत ही बड़े गैंग का हाथ है। इस गैंग ने यूपी में ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का गोरखधंधा फैला रखा है।

ऐसे होती थी चोरी- पेट्रोल में धांधली करने के लिए 2 से 3 लोग काम पर होते हैं। एक पेट्रोल डालता है तो दूसरा व्यक्ति पैसों का बैग लेकर साथ में खड़ा रहता है। बैग वाले व्यक्ति के पास एक रिमोट होता है। चिप को पेट्रोल डालने वाले नोजल के नीचे लगाया जाता है। जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल डलता है उस समय अपने हिसाब से बैग वाला व्यक्ति रिमोट का बटन दबा देता है। इससे गाड़ी में पेट्रोल डलना तो बंद हो जाता है लेकिन मशीन ग्राहक की मांग के अनुसार पेट्रोल और पैसे दिखाती रहती है। यह चिप और रिमोट बहुत ही आसानी से दिल्ली और कानपुर के बाजारों में एक से दो हजार रुपए में मिल जाते है।

नैरो के साथ वनकर्मियों ने दी दबिश

जुर्डा व लोकेश्वर सिंह के घर पहुंचे वनकर्मी

..रायगढ़, 30 अप्रैल। करीब सप्ताह भर पूर्व स्टेडियम के पीछे रहने वाले पिता व पुत्र को वन्यप्राणियों का शिकार करने व उनके अवशेष को रखने के मामले में गिरफ्तार किया था। ऐसे में लगातार वनकर्मी उनके सहयोगियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां आज एक बार फिर से वनकर्मियों ने जुर्डा व लोकेश्वर सिंह के घर में दबिश दी, लेकिन इस बार वनकर्मियों के साथ खोजी कुत्ता था। उसे जुर्डा के दो घर में ले जाया गया, लेकिन उसने कोई भी संकेत वन्यप्राणियों के अवशेष रखने का नहीं दिया। ऐसे में वन विभाग की टीम को बैरंग लौटना पड़ा।

विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि बिलासपुर अचानकमार टाईगर रिजर्व से मंगवाया गया स्नीफर डॉग नैरो के साथ वनकर्मी जुर्डा निवासी मनोज गुप्ता के घर पहुंचे। जहां उसे घर की बाड़ी में ले जाया गया और वन्यप्राणियों के अवशेष ढूंढने का इशारा किया गया। इसके बाद नैरो पूरी बाड़ी में खोज किया, पर यहां उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद यहीं रहने वाला श्रीपुरारी के घर की बाड़ी में ले जाया गया, लेकिन यहां भी उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद स्नीफर डॉग को पूर्व में पकड़े गए शिकारी लोकेश्वर सिंह के घर ले जाया गया। ताकि कुछ वन्यप्राणियों का अवशेष अगर उसने जमीन के भीतर यह किसी अन्य स्थान में छिपाया हो, तो उसे बरामद किया जा सके, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद वन विभाग की टीम बैरंग लौट आयी।

पहली बार ऐसा हुआ है कि वन मंडल रायगढ़ में किसी स्नीफर डॉग को शिकारियों को पकड़ने के लिए लाया गया है। वहीं विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि नैरो (स्नीफर डॉग) का यह पहला केस है। यह भी बताया जा रहा है कि लोकेश्वर सिंह के साथ अन्य लोगों का नाम भी शिकार के लिए आ रहा था। ऐसे में जल्द ही वहां भी दबिश देने की बात कही जा रही है। वहीं इस संबंध में डीएफओ विजया रात्रे ने बताया कि कई बार कार्रवाई के डर से शिकारी वन्यप्राणियों के अवशेष को बाड़ी व घर से बाहर छिपा देते हैं। ऐसे में आज जुर्डा के दो घरों में स्नीफर डॉग के द्वारा जांच की गई। हांलाकि वहां कुछ भी नहीं मिल सका है।

तेंदूपत्ता संग्रहको के लिए कई योजनाएं

1500 रुपए से 1800 मानक बोरा दर दिया जाएगा

रायगढ़. आज के इस आधुनिक युग में ग्रामीण क्षेत्र के कई परिवार ऐसे हैं, जो जंगल पर आश्रित रहना छोड़ दिए हैं। ऐसे में कई बार तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन शासन ने नई योजना के तहत संग्रहको को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले बार की अपेक्षा संग्रहण दर मानक बोरा का मुल्य ग्रामीणों को लाभ देने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब संग्रहको को 1500 रुपए के बदले 1800 रुपए मानक बोरा के दर से दिया जाएगा। इसके साथ ही विभाग के द्वारा संग्रहण का कार्य के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है।

विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण का दर बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के संग्रहक जुड़ रहे हैं और तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 सीजन का में 46242 सग्रहका का बोनस 37880460 रुपयों का नगद रूप में 4176000 रुपए धनादेश द्वारा 3374460 रुपए वितरण किया गया। विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि संग्रहको को लाभ दिलाने के लिए शासन के द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान लाभ दिलाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है। इस वर्ष संग्रहको को परिचय पत्र भी दिया जा रहा है। ताकि तेंदूपत्ता के संग्रहको को पहचाना जा सके। वहीं बताया जा रहा है कि बूटा कटाई का कार्य पहले ही कर लिया गया था और अब एक मई से तेंदूपत्ता संग्रहण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग के द्वारा संग्रहको को पूर्व में कार्यशाला के दौरान अच्छे क्वालिटी के पत्ते पहचनाने व संग्रहण के लिए कई प्रकार की जानकारी दी गई थी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल सौ मानक बोरा कम लक्ष्य दिया गया है और इस बार का लक्ष्य 63800 मानक बोरा दिया गया है। जिसकी पूर्ति कर लेने की बात अधिकारी कर रहे हैं। हर साल विभाग के द्वारा संग्रहको चरण पादुका दिया जाता है। ताकि संग्रहक तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए खाली पैर नहीं जाए। इसके लिए इस साल भी महिला व पुरूषों का चरण पादुका का वितरण किया जाएगा। विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि लगभग 57360 संग्रहको को चरण पादुका दिया जाएगा। विभाग के द्वारा संग्रहको के साथ ही उनके बच्चों के लिए भी कई प्रकार की योजनाए तैयार की गई है। संग्रहको के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। पिछले वर्ष जनश्री छात्रवृत्ति योजना के तहत 5433 छात्र-छात्राओं को 6519600 रुपए का लाभ मिला। प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना के तहत 411 छात्र/छात्राओं को 5340000 राशि का वितरण किया गया। इसके अलावा मेधावी, व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक योजना के तहत भी उन्हें लाभ दिया गया।

शासन के द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहको के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। जिनका लाभ उन्हें दिया जा रहा है। इसके साथ ही अब संग्रहको को 1500 रुपए के बदले 1800 रुपए मानक बोरा का दर दिया जाएगा।

बीएस सरोटे एसडीओ, तेंदूपत्ता विभाग

कोमा-कसही बाहरा जलाशय की पूर्णता के लिए सीएम से मिलेंगे हितेश

छत्तीसगढ़ संवाददाता

महासमुन्द, 30 अप्रैल। अपूर्ण सिंचाई योजनाओं की पूर्णता के लिए लंबे अर्से से आंदोलन चला रहे हितेश चंद्राकर ने इस बात पर चिंता जताई है और कहा है कि यदि कि आने वाले समय में कोमा-कसही बाहरा जलाशय की पूर्णता के लिए क्षेत्र के किसान व क्रेडा अध्यक्ष एवं भाजपा के विधानसभा प्रभारी पुरंदर मिश्रा के साथ मिल कर वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह व सिंचाई मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से भेंट करेंगे। इन्होंने बताया है कि अपूर्ण धरमपुर जलाशय में नाम मात्र का कार्य शेष है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इस जलाशय के लिए क्लयीरेंस मिलने के बाद भी इसे राज्य शासन के बजट में शामिल करने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। जबकि इस बांध के पूर्ण होने से महासमुंद व खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के गांवों के 900 एकड़ से भी अधिक रकबा की सिंचाई होगी। श्री चंद्राकर ने कहा कि वर्ष 2002 में 2.71 करोड़ रुपए की लागत से धरमपुर जलाशय का 64 प्रतिशत शीर्ष कार्य एवं 40 प्रतिशत नहर कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्री चंद्राकर ने एक प्रेस नोट में बताया कि रोक के बाद उन्होंने धरमपुर सहित कोमा व कसहीबाहरा सहित अन्य अपूर्ण जलाशयों की पूर्णता के लिए किसानों के साथ मिल कर आंदोलन किया है जिस पर कलेक्टर द्वारा वन भूमि के एवज में वन विभाग को राजस्व जमीन हस्तांतरित करने के साथ निर्माण की समस्त अड़चनों को दूर कर दिया गया और 1 अगस्त 2016 को बजट में शामिल करने के लिए कुल 9.6 करोड़ रुपए शीर्ष कार्य तथा 1.56 करोड़ रुपए नहर कार्य का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेज दिया है। शीर्ष कार्य की लागत में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा दिए गए डिमांड राशि 8 करोड़ 29 लाख 88 हजार रुपए भी शामिल है। लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्री चंद्राकर ने कहा है कि सिंचाई मूलक ऐसे ही कार्यों से किसानों की आय दोगुनी होगी। इसलिए आने वाले समय में इस जलाशय की पूर्णता के लिए क्षेत्र के किसान व क्रेडा अध्यक्ष एवं भाजपा के विधानसभा प्रभारी पुरंदर मिश्रा के साथ मिल कर वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह व सिंचाई मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से भेंट करेंगे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा. प्र. क्र. 929 अ-2 / 2016-17

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेश जोशी आ. राजेश्वर राव निवासी बिलासपुर छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग. भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 / 59 (2) (5) के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अनुसूची ग्राम / प.ह.नं. जहां भूमि स्थित है कुरुद प.ह.नं. 14/19 अ तहसील व जिला दुर्ग, खसरा नम्बर 1257, रकबा 0.050 हे. / 5437, प्रयोजन आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 13.05.2017 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.04.2017को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27.04.2017

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा. प्र. क्र. 998 अ-2 / 2016-17

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती प्रभा ठाकुर ध.प. दिनेश कुमार ठाकुर निवासी क्वा.नं. 2 ई सड़क 86 सेक्टर-6 भिलाई द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग. भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 / 59 (2) (5) के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अनुसूची ग्राम / प.ह.नं. जहां भूमि स्थित है कोहका प.ह.नं. 14/19 अ तहसील व जिला दुर्ग, खसरा नम्बर 76/59 रकबा 0.020 हे. / 2125 वर्गफीट, प्रयोजन आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 13.05.2017 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.04.2017को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग
दुर्ग दिनांक 27.04.2017

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

रा. प्र. क्र. /अ-6/2015-16

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक श्रीमती जागीर कौर पति स्व. निर्मल सिंह निवासी वार्ड 27 भिलाई तह. व जिला दुर्